प्रतिदिन

पुलवामा हमले का जवाब

पुलवामा के आतंकवादी हमले ने एक नहीं, एक साथ कई बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं. कश्मीर में जिस तरह का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है, उसका जवाब देना कभी आसान नहीं रहा. हर मोर्चे पर एक अलग चुनौती है. सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से यह रही है कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, पर कश्मीर के लोगों को इस लड़ाई में बचाया भी जाए. सेना और सुरक्षा बल हमेशा ही यह कोशिश करते रहे हैं कि आतंकवादियों को तो निशाना बनाया जाए, लेकिन कुछ इस तरह से कि स्थानीय जनजीवन पर इसका ज्यादा असर न पड़े. इसके लिए उसे ढेर सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, आतंकी अक्सर इन्हीं सावधानियों का फायदा उठाते हैं. पुलवामा हमले का जो ब्योरा अब तक सामने आया है, वह यही बताता है कि इसमें जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए दी गई छूट का फायदा उठाया गया. लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए दी गई राहतों को खत्म कर दिया जाए. दरअसल, यह मामला राहत को बनाए रखते हुए सतर्कता को लगातार बढ़ाने का है. इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए, जिससे षड्यंत्रकारी दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सकें?

जब उरी का आतंकवादी हमला हुआ था, तब भारतीय सेना ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की थी. उस जवाबी कार्रवाई का सैनिक महत्व भले ही ज्यादा न रहा हो, लेकिन उससे यह संदेश भेजा गया कि भारत पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकवाद के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा. पर अब कहीं ज्यादा बड़े आतंकवादी हमले ने बता दिया है कि पाकिस्तान ने उस सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ नहीं सीखा है. जाहिर है कि अब हमें इस स्तर से आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा. इस बीच एक यह बयान भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया जाएगा. यह तर्क बहुत समय से दिया जाता रहा है और आतंकवाद से पाकिस्तान का जो रिश्ता है, उसे तकरीबन पूरी दुनिया भी जानती है. इसलिए यह उम्मीद व्यर्थ है कि पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद दुनिया का नजरिया बदल जाएगा. अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के कारण और वहां की स्थितियों को लगातार भड़काते रहने के कारण फिलहाल जो स्थिति है, उसमें पश्चिमी देशों को पाकिस्तान की जरूरत है. ऐसे में, उसे अलग-थलग करना आसान नहीं होगा. ये दो स्थितियां हैं, जिनके बीच में भारत को अपना जवाब तय करना होगा. यह लगभग तय है कि सेना और रक्षा विशेषज्ञों ने जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी होगी. अच्छी बात यह है कि इस मामले पर विपक्ष भी सरकार के साथ खडा दिखाई दे रहा है. ऐसे मौके पर यह भी जरूरी है कि सोशल मीडिया या टीवी की बहसों से सरकार पर किसी खास तरह की कार्रवाई का दबाव न बनाया जाए, फैसले को उस पर छोड़ा जाए.

पुलवामा हमले में सबसे परेशान करने वाली चीज यह है कि पहली बार एक कश्मीरी नौजवान का इस्तेमाल बहुत बडे.आत्मघाती हमले में किया गया. यह बताता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन किस तरह से स्थानीय नौजवानों के दिमाग को दूषित कर रहे हैं. हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस तरह के प्रदूषण को रोकने की है, अलगाववाद की भावना को खत्म करने के लिए यह सबसे जरूरी है.

जल्दबाजी की जरूरत नहीं

एक परिपक्व सरकार सभी विकल्पों को तौलने के बाद अपने चुने हुए समय और स्थान पर तैयारी के साथ कार्रवाई करती है, जब सफलता सुनिश्चित होती है. वह कभी दबाव और अल्पकालिक नतीजे के लिए काम नहीं करती. सरकार का इरादा एक संदेश देना, निडरता पैदा करना और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का निर्माण होना चाहिए.

इससे इनकार नहीं कि अधिकांश आतंकी समूह सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं. हालांकि उन्हें खत्म नहीं किया जा सका है. यह आतंकी हमला अपने चुने हुए स्थान पर हमला करने की उनकी क्षमता को दशार्ता है. ऐसे हमले से उनका मनोबल बढ़ेगा और संभवतः भर्ती भी बढ़ेगी. आतंकवादी उम्मीद करते होंगे कि सुरक्षा बल स्थानीय आबादी के साथ निर्मम होंगे और उन पर संदेह करेंगे. पर ऐसी कार्रवाई दीर्घ काल के लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए सुरक्षा बलों को सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय लोगों के प्रति उनका रवैया न बदले. उन्हें पहले की तरह ही आतंकियों पर हमला और उनके नेतृत्व को खत्म करना चाहिए.

वेलेंटाइन डे को पुलवामा जिले में सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस पर फिदायीन हमला हाल के समय का सबसे बड़ा आतंकवादी आक्रमण है. बेशक यह बेहद दुखद घटना है, लेकिन यह कई पहलुओं को खोलती है, जो विश्लेषण की मांग करते हैं.

पहला तो यही कि इतना बड़ा काफिला कभी भी अलक्षित नहीं हो सकता. जाहिर है, इसकी खबर फैल गई होगी. इसने आतंकी समूहों को आत्मघाती वाहन और हमलावर के चयन का मौका दे दिया होगा, जिसका वीडियो हमले के तुरंत बाद जारी किया गया. जाहिर है, यह हमला सुनियोजित था. आखिरकार विस्फोटकों से लदे एक वाहन को कम समय में तैयार नहीं किया जा सकता. इसलिए सीआरपीएफ की आसन्न गतिविधि की जानकारी लीक होने की पूरी आशंका है, जिसकी पड़ताल की जानी चाहिए.

इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक प्राप्त करने की आतंकियों की क्षमता की भी जांच होनी चाहिए. यह या तो नियंत्रण रेखा के माध्यम से सीमा पार से खरीदा गया होगा या उन संगठनों से हासिल किया गया होगा, जो इसका काम करते हैं. किसी भी मामले में इसकी जांच करने और खामियों को दूर करने की जरूरत है.

दूसरी बात यह है कि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ऐसा हुआ. ऐसे काफिले केवल एक बार सड़क खुलने के दौरान और अपनी सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं. सड़क पर आने वाले वाहनों की जांच की जाती है, फिर भी विस्फोटक लदा वह वाहन अंदर घुसने में कैसे कामयाब रहा? इस पर चिंतन-मनन और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी. इससे संकेत मिलता है कि आतंकियों ने इलाके का सर्वे किया और व्यवस्था की खामियों का उन्हें पता था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया.

हमले के साथ-साथ वाहनों पर गोलीबारी से पता चलता है कि आतंकवादियों ने सही समय पर अपने खुफिया तंत्र का संचालन किया था, जो सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित जानकारियों के लीक होने की पुष्टि करता है. तीसरा मुद्दा यह है कि अपने आपमें यह आत्मघाती हमला ही है. सुरक्षा बलों के शिविरों पर अब तक जो आत्मघाती हमले हुए हैं, उनमें हमलावर ज्यादातर पाक नागरिक रहे हैं. शायद ही कभी कोई कश्मीरी उसमें शामिल रहा हो. यह हमला घाटी में आतंकवाद के पैटर्न में बदलाव का संकेत दे सकता है, इसलिए सुरक्षा बलों को अपनी मौजूदा रणनीति में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है. ऐसी खबरें हैं कि आतंकवादियों को अफगानिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया, जो एक चिंताजनक पहलू है.

चौथा मुद्दा हमले के समय से जुड़ा है. चूंकि लोकसभा का चुनाव करीब है, यह हमला भाजपा की छवि को धूमिल कर सकता है, जो कुछ समय पहले तक पाकिस्तान पर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता और आतंकी घटनाओं पर रोक का दावा कर रही थी. अगर राजनीतिक दलों में पर्याप्त परिपक्वता होगी, तो इस घटना को चुनाव में मुद्दा नहीं बनना चाहिए. हालांकि, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को जानने के बाद कोई भी विरोधी दल सरकार को तुरंत चुनौती नहीं देगा, क्योंकि यह भारतीय भावना की अनदेखी करने जैसा होगा. लेकिन कुछ समय बाद वे सरकार की कश्मीर और पाकिस्तान नीति पर सवाल उठा सकते हैं.

पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. उसने अपनी सेना के निर्देश पर ऐसा किया होगा, जिसका उद्देश्य गुप्त होगा. मुख्य रूप से उसने मौजूदा राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने और स्थानीय आतंकियों की शिथिलता दूर करने के लिए ऐसा किया होगा.

जैसा कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने अंतिम भाषण में कहा कि एक ही पार्टी की बहुमत के सरकार के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान किया जाता है, जिसने राष्ट्र को निर्णायक रूप से कार्य करने की ताकत दी. इसलिए पाकिस्तान भारत में एक मजबूत पार्टी की सरकार के बजाय एक कमजोर गठबंधन की सरकार चाहता होगा. इससे उसे अधिक छूट पाने और अपनी शर्तों पर भारत को वार्ता में शामिल करने का मौका मिल सकता है. पर उसे कामयाब नहीं होने दिया जा सकता.

अगला पहलू घाटी में अलगाव-वादियों का रवैया है. सुरक्षा बलों ने जान गंवाई है और यह राष्ट्र के लिए त्रासदी है. दुख के इस क्षण में भी आतंकवादियों की आलोचना करने से इनकार करना, चुप्पी बनाए रखना और सुरक्षा बलों पर दूसरों की भावनाओं को समझे बिना ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाना राष्ट्रद्रोह के समान है.

सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के राष्ट्रीय निहितार्थ हैं. चूंकि सीआरपीएफ की भर्ती राष्ट्रीय स्तर पर होती है, इसलिए देश भर में शोक की लहर होगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है या घायल हुए हैं, वे देश के लगभग सभी राज्यों से होंगे.इसके राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे.

इससे इनकार नहीं कि अधिकांश आतंकी समूह सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं. हालांकि उन्हें खत्म नहीं किया जा सका है. यह आतंकी हमला अपने चुने हुए स्थान पर हमला करने की उनकी क्षमता को दशार्ता है. ऐसे हमले से उनका मनोबल बढ़ेगा और संभवतः भर्ती भी बढ़ेगी. आतंकवादी उम्मीद करते होंगे कि सुरक्षा बल स्थानीय आबादी के साथ निर्मम होंगे और उन पर संदेह करेंगे. पर ऐसी कार्रवाई दीर्घ काल के लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए सुरक्षा बलों को सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय लोगों के प्रति उनका रवैया न बदले. उन्हें पहले की तरह ही आतंकियों पर हमला और उनके नेतृत्व को खत्म करना चाहिए.

पूरे देश से बदला लेने की मांग उठेगी. सरकार भी जानती है कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमले का समय चुनावों के करीब है. सर्जिकल स्ट्राइक के प्रचार से संकेत मिलता है कि राष्ट्र एक कठोर प्रतिक्रिया की उम्मीद करेगा. बेशक पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को कूटनीतिक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, पर अपने विकल्पों और कार्रवाई पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए. जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है.

एक परिपक्व सरकार सभी विकल्पों को तौलने के बाद अपने चुने हुए समय और स्थान पर तैयारी के साथ कार्रवाई करती है, जब सफलता सुनिश्चित होती है. वह कभी दबाव और अल्पकालिक नतीजे के लिए काम नहीं करती. सरकार का इरादा एक संदेश देना, निडरता पैदा करना और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का निर्माण होना चाहिए. संदेश यह भी होना चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयां भारत को प्रभावित नहीं कर सकती हैं.

हर्ष कक्कड़. सेवानिवृत्त मेजर

इंटरनेशनल मीडिया

मीडिया पर बढ़ते हमले

फिलीपींस की निर्भीक पत्रकार और समाचार संगठन रैपलर की संस्थापक प्रमुख मारिया रेसा की गिरफ्तारी एक शर्मनाक घटना है. राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते और उनके समर्थक ऐसे किसी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो उन्हें ‘वार ऑन ड्रग्स' के संदर्भ में जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है. मारिया रेसा को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया, उससे संबंधित कानून उनके कथित अपराध के महीनों बाद वजूद में आया. अब सबसे पहले उन्हें कर चोरी के मामले में जमानत लेनी पडेगी, जिसके बारे में उनका कहना है कि रैपलर को प्रताड़ित कर खामोश करने के लिए यह मुकदमा गढ़ा गया है. इस न्यूज संगठन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इसके राजनीतिक संवाददाता को राष्ट्रपति भवन के संवाददाता सम्मेलन में शिरकत करने पर रोक लगा दी गई है. रेसा का कहना है कि रैपलर के खिलाफ सरकार की कार्रवाई एक प्रकार से उसकी तारीफ ही है. यह साबित करती है कि राष्ट्रपति इसे एक खतरे के तौर पर देखते हैं.

ताकतवर लोगों के पास अपने आलोचकों को खामोश करने की वजहें हैं. सऊदी स्तंभकार जमाल खाशोगी उन 80 पत्रकारों में एक थे, जिन्हें पिछले साल मार डाला गया, जबकि सैकड़ों अन्य खबर-नवीसों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया. घाना के जिस पत्रकार ने फुटबॉल के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, उसे इसी जनवरी में गोली मार दी गई. पिछले ही हफ्ते दो अफगान पत्रकारों को उनके रेडियो स्टेशन में गोलियों से भून डाला गया था. इसी सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में बीबीसी के एक कैमरामैन के साथ धक्कामुक्की और गाली-गलौज की गई. हालांकि बाद में व्हाइट हाउस के एक बयान में इस हिंसा की भत्र्सना की गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कांग्रेस सदस्य ग्रेग ग्लेनफोर्ट के एक अभद्र कृत्य की सराहना की थी. ग्लेनफोर्ट ने ‘द गार्जियन' के एक पत्रकार के साथ मारपीट की थी. पत्रकारों के लिए हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं. ‘कौंसिल ऑफ यूरोप' ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 2018 को प्रेस की आजादी के लिहाज से सबसे खराब साल माना है.

द गार्जियन, ब्रिटेन.

जान लुटाकर चले गये

पहचान मिटाकर चले गये/ पल-पल की खुशियां/अरमान लूटा कर चले गये/ एक तमन्ना लिये दिल में/मेरा भारत खुशहाल रहे/ इसलिये हिन्दुस्तां पर/अपनी जान लुटाकर चले गये.

और अब...

हिफाजत में मेरी शहीद हुए तुम जिस पथ पर/शहादत से मेरी फिर लहुलुहान वह पथ होगा/ फर्क बस यह होगा कि...दुश्मन के धड़ होंगे चरणों में तेरे/ फर्क से सीना चौड़ाकर खड़ा मेरा हिन्दुस्तान होगा।

महेश धनराज मुलचंदानी.

प्रतिदिन

प्रेमचंद की गाय

उन दिनों प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक मुंशी प्रेमचंद गोरखपुर में अध्यापक थे. उन्होंने अपने यहाँ गाय पाल रखी थी. एक दिन चरते-चरते उनकी गाय वहाँ के अंग्रेज जिलाधीश के आवास के बाहर वाले उद्यान में घुस गई. अभी वह गाय वहाँ जाकर खड़ी ही हुई थी कि वह अंग्रेज बंदूक लेकर बाहर आ गया और उसने गुस्से से आग बबूला होकर बंदूक में गोली भर ली. उसी समय अपनी गाय को खोजते हुए प्रेमचंद वहाँ पहुँच गए. अंग्रेज ने कहा- यह गाय अब तुम यहाँ से ले नहीं जा सकते. तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने जानवर को मेरे उद्यान में घुसा दिया. मैं इसे अभी गोली मार देता हूँ, तभी तुम काले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि हम यहाँ हुकमत कर रहे हैं. और उसने भरी बंदूक गाय की ओर तान दी. प्रेमचंद ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की- महोदय इस बार गाय पर मेहरबानी करें. दूसरे दिन से इधर नहीं आएगी. मुझे ले जाने दें साहब यह गलती से यहाँ आई. फिर भी अंग्रेज झल्लाकर यही कहता रहा- तुम काला आदमी ईडियट हो, हम गाय को गोली मारेगा. और उसने बंदूक से गाय को निशान बनाना चाहा. प्रेमचंद झट से गाय और अंग्रेज जिलाधीश के बीच में आ खड़े हुए और गुस्से से बोले- तो फिर चला गोली. देखें तुझमें कितनी हिम्मत है. ले पहले मुझे गोली मार. फिर तो अंग्रेज की हेकड़ी हिरन हो गई. वह बंदूक की नली नीची कर अपने बंगले में घुस गया.

नेटीजन

ताकि कश्मीर में शांति हो

कश्मीर घाटी में आतंकियों के खात्मे का अभियान जारी रखने के अलावा हुर्रियत के सभी गुटों को प्रतिबंधित करके उनके तमाम नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें देश के दूरदराज की जेलों में डाल दिया जाए, तो घाटी की 80 प्रतिशत समस्या का फौरी समाधान संभव है.

दिमाग भले आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के हों, मगर आतंक को जमीन पर उतारने वाले हमारे अपने ही देश के युवा हैं. घाटी में सक्रिय ज्यादातर आतंकी कश्मीरी हैं. उनके समर्थन में सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाने वाले भी कश्मीरी हैं. पाकिस्तान के पैसे से भारत-विरोधी गतिविधियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संचालन करने वाले और हाथों में पाकिस्तानी झंडे देकर पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने वाले हुर्रियत के तमाम लोग कश्मीरी हैं. पिछले तीन दशकों का अनुभव बताता है कि सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, कश्मीर को कत्लगाह में तब्दील कर डालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना उनके बस की बात नहीं है. इसके लिए इंदिरा गांधी जैसी एक दबंग नेता की जरूरत है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नहीं दिखता. यह जरूर है कि हमारी सरकार यदि चाहे, तो अपना घर जरूर ठीक कर सकती है. अगर कश्मीर घाटी में आतंकियों के खात्मे का अभियान जारी रखने के अलावा हुर्रियत के सभी गुटों को प्रतिबंधित करके उनके तमाम नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें देश के दूरदराज की जेलों में डाल दिया जाए, तो घाटी की 80 प्रतिशत समस्या का फौरी समाधान संभव है. क्या अपनी सरकार से हम इतनी भी उम्मीद नहीं करें?

ध्रुव गुप्त की फेसबुक वॉल

पुलवामा हमला...

पड़ोसी मुल्क की नई रणनीति का संकेत

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के संकेत मिलते ही पाकिस्तान ने कश्मीर को उबालना शुरू कर दिया है.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के चंद मिनटों के बाद ही जिस तरह से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी खुलेआम जिम्मेदारी ली, उसमें कई संदेश छिपे हैं. पहला यह कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने इस संगठन को अब नए दर्जे के हमले करने का निर्देश दिया है और इस काम में इस्लामाबाद उसकी पूरी मदद भी करेगा. काबुल से अमेरिकी फौज से हटने की घोषणा और तालिबान-अमेरिका वार्ता में मुख्य भूमिका निभाने के कारण उसे अपनी हैसियत बढ़ती हुई दिख रही है. पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लगने लगा है कि यह बाजी उनकी तरफ जा रही है, इसलिए कश्मीर का मसला फिर से जिंदा किया जाए.

इस हमले का दूसरा संदेश यह है कि आतंकी कश्मीर में तालिबान मॉडल अपनाना चाहते हैं. इस मॉडल में आत्मघाती हमलावर ‘वीकल बोर्न इंप्रोवाइज्ड डिवाइस' यानी कार-ट्रक आदि बम द्वारा हमले की रणनीति अपनाता है, जो अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में अधिकतर इस्तेमाल की गई है.अब सीमा पार मौजूद आतंकी संगठन रणनीति बनाएंगे और उसे अंजाम देने में स्थानीय लड़कों का इस्तेमाल किया जाएगा.

पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से हिज्बुल मुजाहिदीन जैसी स्थानीय तंजीमों के बूते घाटी को अशांत करने में जुटा था. लेकिन इसमें उसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी. संगठनों में स्थानीय रंगरूटों की भरती तो हो रही थी, लेकिन पूरी तरह दक्ष न होने के कारण वे भारतीय सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ते जा रहे थे. इसीलिए पाकिस्तान अब ‘पार्टनरशिप' में आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहा है. पुलवामा हमले को ही जैश ए मोहम्मद ने स्थानीय सीश्रेणी के लड़ाके के जरिए अंजाम तक पहुंचाया है. आतंकी संगठन भारत में इस तरह के और हमले कर सकते हैं. हमारे सुरक्षा बलों को इन नई रणनीतियों से पार पाना होगा. इसके लिए समग्र नीति बनानी होगी.

अब फिर से ‘सर्जिकल स्ट्राइक' की मांग होने लगी है. लेकिन महज एक कार्रवाई से सीमा पार बैठे आतंकियों या दुश्मन देश को सबक नहीं सिखाया जा सकता. मेजर जनरल बीसी खंडूरी की अध्यक्षता वाली रक्षा पर बनी संसद की स्थाई समिति ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किए जा रहे. ऐसी रिपोर्ट भी आई हैं कि भारतीय सेना के पास दस दिनों के युद्ध के लिए भी गोला-बारूद नहीं है और सुरक्षा बलों के 68 फीसदी साजो-सामान ‘विंटेज कैटेगरी' यानी पुरानी श्रेणी के हैं. ऐसे में, भला हम कैसे प्रभावशाली जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे? लिहाजा, हमें सबसे पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. फिर, कश्मीर के लोगों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है. स्थिति यह है कि उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों को किनारे किया जा रहा है और उनकी सरकार अस्थिर कर दी गई है. ऐसी सूरत में आतंकियों की बदली रणनीति से पार पाना हमारे लिए काफी मुश्किल चुनौती हो सकती है.

अजय साहनी.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर ‘प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com ‘प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.